भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 584

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है

स्थानीय विकास में कोयला खानों का योगदान

584. श्री चंदन चौहान:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्री जुगल किशोर:
श्री काली चरण सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड और अरूणाचल प्रदेश में ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय विकास को सुदृढ़ करने में आम्रपाली-मगध और नामचिक-नामफुक कोयला खानों के उद्देश्य और अपेक्षित योगदान क्रमशः क्या है;

(ख) इन खानों से कितने आरक्षित भंडार, वार्षिक राजस्व और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होने की प्रत्याशा है;

(ग) मिशन ग्रीन कोल रीजन के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संतुलन और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाएं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और समावेशी क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण का किस प्रकार समर्थन करती हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : झारखंड में मगध और आम्रपाली खानें मिलकर वर्ष 2024-25 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 50% का योगदान करती हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के विज़न के तहत विद्युत उत्पादन के लिए सुनिश्चित कोयला आपूर्ति के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलती है। मगध और आम्रपाली कोयला खानों में क्रमशः 854.91 मि.ट. और 456.34 मि.ट. अनुमानित खनन योग्य भंडार है और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2,812 करोड़ रुपये और 2,367 करोड़ रुपये का निवल बिक्री राजस्व सृजित

होने की अपेक्षा है। ये खानें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) और आस-पास के ग्रामीणों को रोजगार तथा आजीविका में सहायता देकर स्थानीय विकास में योगदान करती हैं। मगध-संघमित्रा क्षेत्र में 808 और आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र में 210 लोगों को पहले ही रोजगार देने का अनुमोदन मिल चुका है।

नामचिक नामफुक कोयला खान प्रति वर्ष 0.2 मिलियन टन (एमटीपीए) कोयले का योगदान करते हुए अरुणाचल प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह स्थिर आपूर्ति राज्य की ऊर्जा मांगों को अधिक विश्वसनीयता से पूरा करने में सहायता करेगी। इस खान में 14.97 मि.ट. के भूगर्भीय भंडार होने का अनुमान है। इस खान से 173 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व सृजित होगा और इससे लगभग 270 लोगों को रोजगार मिलेगा।

(ग) : मिशन ग्रीन (प्रकृति का विकास, पुनर्स्थापन, संर्वधन और सशक्तिकरण) कोयला क्षेत्रों के अंर्तगत, कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने कोयला और लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करने तथा सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। यह मिशन खनन के बाद और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों को संधारणीय पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करने के लिए पांच वर्षीय विजन की रूपरेखा प्रदान करता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, यह मिशन खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास व्यापक वनीकरण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, संधारणीय खान-जल उपयोग और चक्रीय संसाधन प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने के लिए खान-आधारित पर्यटन और हरित-अर्थव्यवस्था मॉडल जैसी पहलों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। सामुदायिक भागीदारी मिशन ग्रीन का एक मुख्य घटक है। इन प्रयासों में संधारणीय विकास कार्यकलापों में स्थानीय समुदायों और स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) की भागीदारी शामिल हैं। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, कोयला मंत्रालय ने मिशन ग्रीन कोयला क्षेत्रों की नियमित निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया है।

(घ) : झारखंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में उपर्युक्त तीन कोयला खानें आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करके भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। खानों के विकास से परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसी सहायक अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश भी होगा, जो व्यापक रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा। यह एकीकृत विकास दृष्टिकोण क्षेत्रों में समावेशी विकास और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा।

****